नए वित्तीय वर्ष में स्थापित होंगे 660 चार्जिंग स्टेशन

जासं, लखनऊ : जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल के साथ चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने का जोर पड़ता जा रहा है। वाहनों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इंडियन आयल अगले वित्तीय वर्ष में करीब 660 चार्जिंग प्वाइंट लगाने जा रहा है। इनमें से करीब दो सौ फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे।

फास्ट चार्जिंग स्टेशन बीस किलोवाट के होंगे और करीब पचास मिनट में वाहन को चार्ज कर देंगे। एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद ढाई सौ से पौने तीन सौ किलोमीटर तक जाया जा सकेगा। इंडियन आयल की योजना दो साल यानी 2026 तक करीब 2600 स्टेशन लगाने की है। अगर कंपनी की योजनानुसार समय से चार्जिंग प्वाइंट लग गए तो सड़कों पर काफी हद तक चार्जिंग करने की दिक्कत कम हो जाएगी। प्रदेश में करीब साढ़े पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का अब तक पंजीकरण हो चुका है। पिछले कुछ सालों में कई कार कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन ही बना रही हैं।

इंडियन आयल की योजना प्रत्येक जिले में चार्जिंग की सुविधा अपने पंपों पर उपलब्ध कराने की है। दरअसल इलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए अलग से स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनी की योजना है कि अगले दो-तीन साल में सभी एक्सप्रेस वे और हाइवे चार्जिंग स्टेशनों से कवर हो जाएं।

इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध में आगे बढ़ा परिवहन निगम

जासं, लखनऊ : इलेक्ट्रिक बसों का अनुबंध करने के लिए परिवहन निगम ने और कदम बढ़ाया है। प्री बिड कांफ्रेंस में करीब डेढ़ दर्जन निवेशकों ने टेंडर से जुड़ी समस्याएं व सुझाव दिए हैं। रोडवेज पहले चरण में 5000 बसों का अनुबंध कर रहा है। इसी माह अनुबंधित इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर लेकर टेक्निकल बिड खोलने की तैयारी है। प्रदेश को प्रदूषणमुक्त बनाने व यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 50 हजार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बनाने को प्रयासरत है, पहले चरण में 5000 बसों का अनुबंध कर रहा है। यूपी से इन बसों की डिमांड पूरी न होने पर अन्य राज्यों की इलेक्ट्रिक बसों से अनुबंध करके उनका संचालन कराया जाएगा। अनुबंधित बसों के मालिकों को बसों की मरम्मत आदि कराने के साथ ही आधारभूत ढांचा भी तैयार कराना होगा। यानी तय मार्गों पर जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। परिवहन मुख्यालय पर आयोजित प्री बिड कांफ्रेंस में निवेशकों ने कहा कि प्रदेश में 2300 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए कंडक्टर भी उन्हीं को देने का मौका मिले। इलेक्ट्रिक बसों की अधिकांश कंपनियां नई हैं ऐसे में तीन साल का अनुभव कहां से लाएं? इसी तरह से अन्य कई सुझाव मिले और कई ने लिखकर भेजा है। अब उच्च स्तरीय समिति इन सुझावों पर निर्णय लेगी। 28 मार्च तक 5000 बसों के लिए अपराह्न तीन बजे तक टेंडर मांगे गए हैं। उसी दिन शाम चार बजे टेक्निकल टेंडर खोले जाएंगे। घोषणा अब लोस चुनाव के बाद ही हो सकेगी।